आकाशवाणी श्री विजयपुरम

दिनांक : 01.02.2025 समय : 1950

<><><><><><><>

- केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने आज संसद में केन्द्रीय बजट पेश किया। कहा –मध्यम वर्ग को राहत देना सरकार का लक्ष्य।
- नई व्यवस्था के अंतर्गत बारह लाख रूपये तक कोई आयकर देय नहीं होगा।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि केन्द्रीय बजट एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- द्वीपसमूह के सांसद बिष्णु पद रे ने कहा कि बजट बचत और निवेश को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

<><><><><><><>

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज संसद में केन्द्रीय बजट दो हजार पच्चीस–छब्बीस प्रस्तुत किया। यह एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इसका लक्ष्य विकास में तेजी लाना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, निजी क्षेत्र में निवेश में वृद्धि और देश के मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता बढ़ाना है। उन्हों़ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था सभी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मध्यम वर्ग भारत के विकास के लिए शक्ति प्रदान करता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्र निर्माण में मध्यम वर्ग की सराहनीय ऊर्जा और क्षमता में विश्वास जताया है। वित्त मंत्री ने कहा कि नई कर व्यवस्था के अंतर्गत बारह लाख तक की आय पर कोई कर देय नहीं होगा।

इसमें विशिष्ट– दर आय जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर एक लाख रूपए प्रति माह की औसत आय पर कोई कर देय नहीं होगा। वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा पचहत्तर हजार की मानक कटौती के कारण बारह लाख पचहत्तर हजार होगी। सभी करदाताओं को फायदा पहुंचाने के लिए सभी श्रेणियों में कर स्लैब और दरों में परिवर्तन करने के प्रस्ताव हैं। बजट में औषधि और दवाओं के आयात पर राहत देने का प्रस्ताव किया गया है। विशेष रूप से कैंसर, असाधारण रोगों और अन्य गंभीर जीर्ण रोगों से पीड़ित रोगियों को राहत देने के लिए छत्तीस जीवन रक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा–शुल्क से पूरी तरह छूट प्राप्त दवाओं की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। बजट में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण और एक करोड़ 70 लाख किसानों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए चुने हुए सौ जिलों में प्रधानमंत्री धन–धान्य कृषि योजना शुरू की जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण सीमा तीन लाख रूपए से बढ़ाकर पांच लाख रूपए करने का प्रस्ताव। लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण के लिए निवेश की सीमा ढाई गुणा बढ़ाने और कारोबार सीमा भी दोगुनी करने का प्रस्ताव। स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी एक प्रतिशत इजाफे के साथ बढ़ाकर बीस करोड़ रूपए करने का प्रस्ताव। वित्तमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना के आधार पर, देश को 'वैश्विक खिलौना केंद्र' बनाने की योजना कार्यान्वित की जाएगी। इस योजना से 'मेड इन इंडिया' ब्रांड का प्रतिनिधित्व करने वाले उच्च गुणवत्ता वाले अनूठे, नवीन और पर्यावरण अनुकूल खिलौने बनेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार एक संशोधित उड़ान स्कीम शुरू करेगी ताकि अगले दस वर्षों में एक सौ बीस नए गंतव्यों के साथ क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके और चार करोड़ यात्रियों को ऐसी परिवहन सुविधा दी जा सके।

<><><><><><><>

वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप जैसे द्वीपों पर विशेष ध्यान देने के साथ भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और गहरे समुद्रों से निरंतर मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेमवर्क लाएगी। इसके अलावा बजट में सामुद्रिक उद्योग के लिए दीर्घावधि धन उपलब्ध कराने के वास्ते पच्चीस हजार करोड़ रुपए की निधि के साथ एक सामुद्रिक विकास निधि स्थापित की जाएगी। वित्त मंत्री ने देश में अन्तर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा टन भार कर योजना के लाभों को भारतीय पोत अधिनियम, दो हजार इक्कीस के अंतर्गत पंजीकृत अन्तर्देशीय जलयानों के लिए विस्तारित करने का प्रस्ताव किया।

<><><><><><><>

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्रीय बजट दो हजार पच्चीस–छब्बीस, एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संसद में बजट पेश किए जाने के बाद अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट भारत की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। श्री मोदी ने बजट को सशक्त बनाने वाला बताया और कहा कि यह देश में बचत, निवेश, खपत और विकास को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस बजट से देश के मध्यम वर्ग को बहुत लाभ होगा क्योंकि बारह लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह कृषि क्षेत्र को सशक्त करेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा।

<><><><><><><>

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि केंद्रीय बजट कृषि, ग्रामीण समृद्धि तथा शहरी विकास पर केंद्रित है और इसमें लगातार सुधारों पर जोर दिया गया है। नई दिल्ली में संवददाताओं से बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा कि छह निर्दिष्ट सुधारों की पहचान की गई है, जिनमें सरकार अपने सुधार एजेंडे को जारी रखेगी। सुश्री सीतारामन ने कहा कि बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा के हितों को प्राथमिकता दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले जुलाई में घोषित आयकर सरलीकरण का काम पहले ही पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में नया आयकर विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा।

<><><><><><><>

अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद बिष्णु पद रे ने केंद्रीय बजट दो हजार पच्चीस की सराहना की है। एक बयान कर उन्होंने कहा यह लोगों के अनुकूल बजट है, जो बचत और निवेश को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इससे होमस्टे मालिकों के लिए मुद्रा ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा का स्वागत करते हुए सांसद ने कहा कि ग्रामीण और उभरते पर्यटन स्थलों में आतिथ्य सेवाओं में बढ़ोत्तरी होगी। श्री रे ने कहा कि इससे द्वीपों में नए उद्यमियों को बहुत मदद मिलेगी।

जवाहर लाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय की अर्थशास्त्र विभाग की विभागाध्यक्षा हेमा बैनर्जी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

<><><><><><><>

डॉ. बी आर अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में कौशल विकास पहल के तहत, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभागों के छात्रों के लिए कार्यशाला इंटर्नशिप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान, छात्रों को बढ़ईगीरी, वेल्डिंग और शीट मेटल पर कार्य करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर छात्रों ने प्रत्येक ट्रेड में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया।

<><><><><><><>